BACHPAN EXPRESS
बचपन एक्सप्रेस

डाक पंजीयन संख्याः
एस.एस.पी/एल.डब्लू/एन.पी.-571/2018-2020

मासिक समाचार पत्र

UPBIL/2017/73837 | वर्ष : 4 | अंक: 41 | लखनऊ, अक्टूबर 2020 | पृष्ठ 8 | मूल्य 20/-

पीएम मोदी ने 100 रुपए का स्मृति सिक्का किया जारी

सुरक्षित, समृद्ध भारत के सपने को करेंगे पूरा

(एजेंसी)

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की संस्थापक सदस्य रहीं ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया के जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में 100 रुपये का स्मृति सिक्का जारी किया और कहा कि सुरक्षित, समृद्ध भारत के उनके सपने को केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत की सफलता से पूरा करेगी। वीडियो कांफ्रेंस से आयोजित इस समारोह में सिंधिया परिवार के सदस्यों के साथ-साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों सहित देश के अन्य भागों से कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए कश्मीर को लेकर या फिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए उनके संघर्ष हों, उनकी जन्मशताब्दी के साल में ही उनके ये सपने भी पूरे हुए। राजमाता सिंधिया को त्याग

और तपस्या की प्रतिमूर्ति बताते हुए मोदी ने कहा कि उनके पास सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं, इसके बावजूद उन्होंने आम लोगों और गांव, गरीब के साथ जुड़कर जीवन जिया उनके लिए अपना जीवन समर्पित किया उन्होंने कहा, ''राजमाता ने साबित किया कि जनप्रतिनिधि के लिए राजसत्ता नहीं, जनसेवा सबसे महत्वपूर्ण है। वह एक राज परिवार की महारानी थी लेकिन राष्ट्र के भविष्य के लिए राजमाता ने अपना वर्तमान समर्पित कर दिया था। देश की भावी पीढ़ी के लिए उन्होंने अपना हर सुख त्याग दिया था। राजमाता ने पद और प्रतिष्ठा के लिए न कभी जीवन जिया ना ही कभी राजनीति की। प्रधानमंत्री ने कहा, ''राजमाता के आशीर्वाद से देश आज विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। गांव, गरीब, दलित-पीड़ित-शोषित-वंचित, महिलाएं आज देश की पहली प्राथमिकता में हैं। राजमाता के सपनों को पूरा करने के लिए हम सभी को इसी गति से आगे बढ़ना है। सुरक्षित और समृद्ध भारत उनका सपना था और उनके सपनों को हम आत्मनिर्भर भारत की सफलता से पूरा करेंगे।'' मोदी ने कहा कि राजमाता सिंधिया ने एक पाठ यह भी पढ़ाया कि जन सेवा के लिए किसी ''खास परिवार'' में जन्म लेना ही जरूरी नहीं होता। उन्होंने कहा, ''कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति जिसके भीतर योग्यता है, प्रतिभा है, देश सेवा की भावना है, वह इस लोकतंत्र में सत्ता को भी सेवा का माध्यम बना सकता है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान राजमाता के जीवन से जुड़ी अपनी यादें भी साझा की और कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आजादी के इतने दशकों तक, भारतीय राजनीति के हर अहम पड़ाव की वो साक्षी रहीं। उन्होंने कहा, ''आजादी से पहले विदेशी वस्त्रों की होली जलाने से लेकर आपातकाल और राम मंदिर आंदोलन तक, राजमाता के अनुभवों का व्यापक विस्तार रहा है।'' उन्होंने कहा कि यह अद्भुत संयोग ही है उनकी जन्म शताब्दी के साल में ही कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा और राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया था, उनका यह सपना भी पूरा हुआ। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रह्लाद पटेल ने इस मौके पर कहा कि राज परिवार में जन्म लेकर लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करने वालीं राजमाता विजया राजे सिंधिया एक विरल व्यक्तित्व थीं। उन्होंने कहा, ''वे वात्सल्य की प्रतिमूर्ति थीं। अपने सार्वजनिक जीवन में उन्होंने गरीबों, वंचितों, पीड़ितों के लिए निरंतर कल्याणकारी कार्य किए।'' विजयाराजे सिंधिया ग्वालियर राजघराने की राजमाता होने के साथ-साथ भाजपा की संस्थापक सदस्यों में से एक रही थीं। वह पांच बार लोकसभा और एक बार राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित हुई थीं। विजया राजे सिंधिया का जन्म 12 अक्टूबर 1919 को मध्य प्रदेश के सागर में हुआ था। उनके बेटे माधव राव सिंधिया कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे।

दिल्ली में भीख मांगने वालों पर लगेगी रोक, भिखारियों के पुनर्वास की योजना

(एजेंसी)

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शहरी बेघर भिखारियों के पुनर्वास के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ रविवार को एक बैठक की। इस बैठक में भिखारियों के पुनर्वास के लिए कार्य योजना तैयार करने के विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में दिल्ली पुलिस, दिल्ली सुधार आश्रय बोर्ड के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम ने कहा, यह बैठक दिल्ली में भीख की रोकथाम और भिखारियों के पुनर्वास के लिए एक व्यापक कार्ययोजना बनाने के विषय पर हुई थी।

इनके लिए एक सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास रणनीति बनाने और समाज में व्यापक जन जागरण तथा नागरिकों को शिक्षित करने का कार्यक्रम करने की आवश्यकता है। समाज कल्याण मंत्री ने इस विषय से जुड़े सभी हितधारकों से एक व्यावहारिक मॉडल को अपनाने की अपील की, जिससे सही तरीके से एक दिशा परिणामोन्मुखी प्रयास किए जा सके। इस बैठक में उपस्थित विभिन्न हितधारकों ने भी इस बात पर आम सहमति प्रकट की कि इस समस्या के उन्मूलन के लिए सभी सरकारी विभागों, संस्थानों और नागरिकों के बीच एक बेहतर तालमेल होना आवश्यक है। समाज कल्याण मंत्री ने कहा, भिखारियों के सफल पुनर्वास के लिए एक लक्षित ढंग से प्रयास करने के लिए एक सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक है। राजधानी में भिखारियों की संख्या को निश्चित करने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण समय की मांग है। इस सर्वेक्षण के आधार पर ही ऐसे जटिल विषय के समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा। इस प्रकार के सर्वेक्षण से ही विभिन्न पृष्ठभूमि, आयु और वर्ग के भिखारियों और असहाय तथा कमजोर व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावी उपाय करने के लिए एक आधार प्राप्त होगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक सामाजिक और आर्थिक कारणों पर ध्यान दिए बिना भीख मांगने वालों की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इस बैठक में मौजूद सभी हितधारक इस बात पर एकमत थे कि भीख मांगने वाले व्यक्तियों की वास्तविक संख्या को जानने के लिए एक नया सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। इस सर्वेक्षण में भिखारियों की विभिन्न श्रेणियों - आयु, वर्ग, पृष्ठभूमि - की जानकारी एकत्र करने का प्रावधान होना चाहिए। इससे भिखारियों के पुनर्वास के लिए प्रभावी ढंग से उपाय करने में सहायता मिलेगी। इस विषय में मानक दिशानिर्देशों की अपेक्षित उपलब्धता की बात भी ध्यान में लाई गई। इन सभी उपायों के आधार पर ही भिखारियों की अधिकता वाले क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से समस्या के समाधान की दिशा में कार्य संभव हो सकेगा।दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष अनुराग कुंडू ने कहा, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी के अभाव में बच्चों को होने वाली कठिनाइयों से संबंधित एक अध्ययन प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया कि अपेक्षित सूचना के अभाव में बच्चे सरकारी परियोजनाओं का लाभ लेने से वंचित रहते हैं।

महिलाओं के खिलाफ अपराध के हर मामले में कार्रवाई अनिवार्य : गृह मंत्रालय

(एजेंसी) नई दिल्ली। महिलाओं के खिलाफ देश भर में बढ़ते अपराध विशेष रूप से यौन हिंसा की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी कर कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के हर मामले में सभी नियमों का पालन करते हुए अनिवार्य कार्रवाई की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पिछले महीने एक युवती की मौत और उसके साथ कथित बलात्कार की घटना तथा देश के कुछ अन्य हिस्सों में भी महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में पुलिस की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों के बीच गृह मंत्रालय के महिला सुरक्षा विभाग ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को परामर्श जारी किया है। परामर्श

की प्रति सभी पुलिस महानिदेशकों तथा पुलिस आयुक्तों को भी भेजी गयी है। मंत्रालय ने कहा है कि वह इससे पहले भी समय समय पर इस तरह के परामर्श जारी कर चुका है और फिर से यह परामर्श दिया जाता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और विशेष रूप से यौन हिंसा के मामलों में निर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई किया जाना अनिवार्य है। यौन अपराध के मामलों में प्राथमिकी या जीरो प्राथमिकी दर्ज किया जाना अनिवार्य है। कानून में प्रावधान किया गया है कि यौन अपराध के मामलों की जांच दो महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मंत्रालय ने यह भी याद दिलाया है कि कानून में यह भी प्रावधान है कि इन नियमों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सजा तथा अन्य कार्रवाई का भी प्रावधान है। यौन अपराधों के मामले में यह भी नियम है कि पुलिस को सूचना मिलने के बाद पीडिता की सहमति से पंजीकृत चिकित्सक से उसकी जांच करानी चाहिए। पीड़ित के मरने से पहले दिये गये लिखित या मौखिक बयान को भी तथ्य के रूप में माना जाना चाहिए। इन मामलों में फॉरेन्सिक सबूत भी दिशा निर्देशों के अनुरूप एकत्र किये जाने चाहिए और इसके लिए विशेष रूप से उपलब्ध किट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

देश की करोड़ों महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए हमें समाज को बदलना होगा : राहुल गांधी

(एजेंसी)

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाथरस में दलित लड़की से कथित सामूहिक बलात्कार एवं हत्या के मामले को लेकर सोमवार को उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर फिर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पीड़िता के परिवार से उनकी मुलाकात के बाद इस घटना के पीड़ित पक्ष पर आक्रमण किया और अपराधियों की मदद की। पार्टी की ओर से 'स्पीकअप फॉर वूमेन सेफ्टी हैशटैग से चलाए गए सोशल मीडिया अभियान के तहत वीडियो जारी कर राहुल गांधी ने यह भी कहा कि महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए लोग सरकार पर दबाव बनाएं। हाथरस घटना में सरकार का रवैया अमानवीय और अनैतिक है। वे पीड़ित परिवार की मदद करने की बजाए अपराधियों की रक्षा करने में लगे हैं। कांग्रेस नेता दावा किया कि हाथरस घटना में सरकार का रवैया अमानवीय और अनैतिक है। वे पीड़ित परिवार की मदद करने की बजाए अपराधियों की रक्षा करने में लगे हैं। अपने हाथरस जाने से जुड़े घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे उस परिवार से क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा है। आखिर उस परिवार की बेटी की हत्या हुई थी और बलात्कार हुआ था। मैं जैसे ही परिवार से मिला और बातचीत शुरू की, उसके बाद सरकार ने परिवार पर आक्रमण शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अपराधियों की मदद करना सरकार का काम नहीं होता, अपराधियों की रक्षा करना सरकार का काम नहीं होता।

सम्पादकीय

शिक्षा में फर्जीवाड़ा

एक ओर विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं, तो दूसरी ओर फर्जी संस्थानों व डिग्रियों का संजाल भी बढ़ रहा है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 24 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है. नियमों के अनुसार विधायिका से स्वीकृत और आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थाएं ही विश्वविद्यालय शब्द उपयोग करने या इसके समतुल्य होने का उल्लेख करने की अधिकारी होती हैं. फर्जी संस्थाओं में से सात दिल्ली में और आठ उत्तर प्रदेश में हैं, जबकि शेष पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और पुद्दचेरी में हैं. ऐसी किसी भी संस्था को डिग्री जारी करने का अधिकार नहीं है, फिर भी ये विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को गुमराह कर कमाई करते हैं. इसी तरह से फर्जी कॉलेजों का धंधा भी चलता है, जो स्थापित विश्वविद्यालयों से संबद्ध होने का झूठा दावा करते हैं. कुल मिलाकर यह सब ठगी का कारोबार ही है. पिछले साल बड़े पैमाने पर पैसे के बदले डिग्रियां देने के धंधे के खुलासे के बाद शिक्षा मंत्रालय ने एक उच्च-स्तरीय जांच समिति भी गठित की थी. उस प्रकरण में इंजीनियरिंग और कानून की डिग्रियों के साथ पीएचडी डिग्री बेचने का मामला भी सामने आया था तथा इसका नेटवर्क देशभर में पसरा था. अक्सर फर्जी डिग्री बेचने के धंधे में लिप्त लोगों की गिरफ्तारी की खबरें भी आती हैं. लेकिन संगठित माफिया गिरोहों पर लगाम लगाने में कामयाबी नहीं मिली है. बीते दशकों में रोजगार और नौकरी के स्वरूप में बड़े बदलाव हुए हैं. सरकारी नौकरियों की तरह डिग्रियों की पड़ताल की पुख्ता व्यवस्था निजी क्षेत्र में नहीं है. नकली प्रमाणपत्रों के सहारे लोग विदेशों में भी रोजगार पाने की जुगत लगाते हैं. स्थिति की गंभीरता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि बार काउंसिल ऑफइंडिया के प्रमुख ने कुछ समय पहले कहा था कि देश में 30 प्रतिशत से अधिक वकीलों की डिग्रियां फर्जी हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि भारत में 57 फीसदी से अधिक डॉक्टर नकली सर्टिफिक्रेट लेकर दवाइयां दे रहे हैं. स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण तथा सस्ते इलाज के लिए बड़ी संख्या में लोग ऐसे फर्जी डॉक्टरों के पास जाते हैं और अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हैं. आम जन के लिए यह जानना आसान नहीं है कि कौन डॉक्टर या वकील असली है या नकली. यह खतरनाक खेल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी खेला जा रहा है. साल 2018 में देश में 277 फर्जी इंजीनियरिंग कॉलेजों की पहचान की गयी थी, जिनमें से सबसे अधिक देश की राजधानी में थीं. मैट्रिक, इंटर और बीए के सर्टिफिक्रेट खरीदने के पोस्टर-बैनर आपको पूरे देश में हर कस्बे व शहर में मिल सकते हैं. प्रवेश, पाठ्यक्रम, परीक्षा आदि में कदाचार तथा शिक्षा माफिया के विस्तार के साथ फर्जी संस्थाओं व डिग्रियों का बाजार देश के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है.

अर्थव्यवस्था में और सुधार जरूरी

इस वित्त वर्ष में अप्रैल और मई दो महीने पूरी तरह लॉकडाउन रहने से अर्थव्यवस्था ठप रही जून में लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिली, लेकिन उसमें भी बहुत-सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लंबे समय तक बंद रहने के बाद बड़े-बड़े कल-कारखानों को चालू करना इतना आसान नहीं होता हैघ् इसी कारण जून में भी अर्थव्यवस्था लगभग ठप ही रही उसके बाद जुलाई-अगस्त में स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ हालांकि, इसे सामान्य नहीं कहा जा सकता आज भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी कई तरह के प्रतिबंध लागू हैं मांग कम होने से उत्पादन भी कम हो रहे हैं अर्थव्यवस्था में जो सकारात्मक संकेत दिख रहे हैं, दरअसल वह बंदी के बाद फिर से उत्पादन के शुरू होने का असर हैघ् ऐसा तो होना ही था रेलवे में भी मार्च के बाद सुधार होने की बात कही जा रही है, तो यह तो होना ही था, क्योंकि, रेलवे भी लॉकडाउन में ठप पड़ा हुआ थाघ् जब ट्रेनें चलने लगीं, तो रेलवे की आमदनी तो बढ़ेगी ही पिछले साल के मुकाबले भी देखें तो इस वर्ष ज्यादा वृद्धि होनी तय है, क्योंकि पिछले वर्ष की वृद्धि पेंडिंग रह गयी थी, मान लीजिये, किसी उत्पादक को अपने उद्योग के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता थी और उसने लॉकडाउन से पहले रेलवे के जरिये उसे बुक किया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण ट्रेन की आवाजाही रुक गयीघ्, और जैसे ही लॉकडाउन खुला, तो वह सामान उत्पादक तक पहुंचाया गया, तो यह वृद्धि और लॉकडाउन के बाद जो नयी बुकिंग हुई, दोनों के कारण ही रेलवे की स्थिति में सुधार दिखायी दे रहा है, जो स्वाभाविक है, यदि ऐसा नहीं होता, तो चिंता वाली बात होती, अर्थव्यवस्था का अभी जो आंकड़ा आया है, वह अप्रैल-मई-जून की तिमाही का आंकड़ा है, इसकी गहराई से पड़ताल की जरूरत है, जुलाई-अगस्त-सितंबर, जो दूसरी तिमाही है, उसका आंकड़ा नवंबर में आयेगा. इस तिमाही का परिणाम बहुत महत्वपूर्ण होगा, यानी अर्थव्यवस्था में सुधार के आंकड़े को लेकर अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, पहली तिमाही के परिणाम के आधार पर कुछ भी कहना अभी सही नहीं होगा, दूसरी तिमाही और उसके बाद अक्तूबर-नवंबर-दिसंबर तीसरी तिमाही का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण होगा, यदि तिमाही की बात छोड़ भी दें, तो सितंबर मध्य से नवंबर मध्य तक का समय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर अक्तूबर का महीना, दुर्गापूजा, दीवाली और दूसरे पर्व-त्योहारों का मौसम होने से इस समय खूब खरीदारी होती है, नतीजा बिक्री बढ़ती है जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, इसके बाद दिसंबर मध्य से जनवरी मध्य तक का समय भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि नये वर्ष के उपलक्ष्य में भी लोग घूमने-फिरने जाते हैं, खर्च करते है, हालांकि, यह दीवाली के स्तर से छोटा होता है, इस वर्ष लोगों का घूमना तो पहले के मुकाबले कम होगा, लेकिन खरीदारी तो होगीघ् दिवाली और नये वर्ष के उपलक्ष्य में खरीदारी होने की पूरी संभावना है, जो एक अच्छी बात है, यही वो आंकड़े हैं, जो निर्णायक साबित होंगे, अभी यह कहना कि हम लोग सुधार की राह पड़ चल पड़े हैं, बहुत सुधार हो गया है, जल्दबाजी होगी इसके लिए नवंबर वाला और उसके बाद की तिमाही के परिणाम की प्रतीक्षा करनी होगी हर महीने और तीमाही के आंकड़े को बार-बार देखने की अभी जरूरत है इसके बाद ही अगले वर्ष फरवरी-मार्च में हम ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की दशा क्या है फरवरी-मार्च वाली तिमाही में यदि हम नकारात्मक से निकल पाते हैं, शून्य पर भी आ जाते हैं, तभी जाकर हम कह पायेंगे कि अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है जहां तक निर्यात की बात है, तो उससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं दिख रही है निर्यात तो तभी होगा और बढ़ेगा, जब दूसरे देश के लोग खरीदारी करेंगे. महामारी का प्रभाव तो दुनियाभर में पड़ा है ऐसे में निर्यात पर बुरा असर पड़ेगा, वहां किसी तरह के सुधार की संभावना अभी नहीं दिख रही हैघ् यदि निर्यात में थोड़ी-बहुत वृद्धि हो भी जाये, तो वह इतना नहीं होगा कि उससे जीडीपी में वृद्धि दर्ज होघ् क्योंकि अभी जो पहली तिमाही का आंकड़ा आया है, उसके अनुसार, आयात में भी गिरावट आयी है आयात में केवल तेल नहीं आता है, बल्कि बहुत से मशीनरी इक्विपमेंट आते हैघ्, जो आयातित वस्तुओं का बड़ा हिस्सा होते हैं, इसलिए आयात का गिरना अच्छी बात नहीं है खासकर आज की स्थिति में. रोजगार की समस्या अभी भी बरकरार है, क्योंकि बहुत से लोगों की नौकरी चली गयी है अभी जो भी काम-काज हो रहे हैं, जो भी कल-कारखाने चल रहे हैं, वहां भी 50 प्रतिशत कर्मचारियों से ही काम चलाया जा रहा हैघ् पचास प्रतिशत लोगों के पास तो अभी भी काम नहीं है यदि लोगों के पास काम नहीं होगा, तो उन्हें पैसे की तंगी होगी, ऐसे में मांग का सृजन कहां से होगा लोग खरीदारी कहां से करेंगे इसका असर वस्तुओं के उत्पादन पर भी पड़ेगा उत्पादन के कम होने का असर दूसरी तिमाही के आंकड़े में निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा. तो यहां सरकार द्वारा रोजगार सृजन को लेकर काम करने की जरूरत है मांग में वृद्धि हो, इसके लिए लोगों के हाथ में नकद देना बहुत जरूरी है जन वितरण प्रणाली के तहत बीपीएल कार्डधारकों को नि:शुल्क राशन मुहैया कराया जाये, ताकि उनके खाने-पीने की समस्या दूर हो इससे उनके हाथ में जो पैसा बचेगा, उससे हो सकता है कि वह कुछ न कुछ खरीदारी करे साथ ही, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सरकार जो पैसा दे रही है, वह सही हाथों में पहुंचे दूसरा, सभी उद्योगों के लिए सरकार को इनपुट टैक्स, जीएसटी को कम करने की जरूरत है, ताकि उद्योगों के लाभ में थोड़ी वृद्धि हो अभी तक सरकार ने जो पैकेज दिया है, उसमें उपभोक्ता मांग का हिस्सा बहुत कम है. प्रत्यक्ष लाभ के लिए सरकार को आठ लाख करोड़ का पैकेज देने की जरूरत है मनरेगा के आवंटन को बढ़ाने और प्रति बीपीएल परिवार 1500 से 2000 प्रतिमाह नकद भुगतान करने की जरूरत है, इससे अर्थव्यवस्था बच जायेगी इसके अलावा सरकार घरेलू और एनआरआइ के लिए कोविड बॉण्ड जारी करे, फॉरेन क्रेडिट मार्केट में ब्याज दर कम है, वहां से पैसा लेने की कोशिश करे, डेफिसिट फाइनेंस करे और उस पैसे को मार्केट में डाले, तो इससे अर्थव्यवस्था में सुधार होगा।

सर्दियों में कोरोना का खतरा ज्यादा

डॉ ललितकांत

विदेशों से आये लोग जब अपने घरों में पहुंचे, तो वहां से यह संक्रमण उनके यहां काम करनेवाले ड्राइवर, घरेलू सहायकों तक पहुंचा. वे इस बीमारी को अपने-अपने इलाकों तक ले गये. ऐसे ज्यादातर लोग स्लम एरिया में रहते हैं, जहां आबादी काफी सघन होती है. स्लम एरिया में इसे रोकना मुश्किल हो गया. एहतियात के तौर पर, मार्च में ही प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी. इसके बाद दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, पुणे, कोलकाता आदि शहरों से निकले श्रमिकों के माध्यम से संक्रमण देश के दूर-दराज गांवों में फैल गया. गांव-देहात के इलाकों में संक्रमण रोकने की चुनौती और बड़ी है. यहां स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी मुख्य तौर पर पांच गंभीर चुनौतियां हैं. पहली, जनसंख्या के अनुपात में डॉक्टरों की बहुत कमी है. देश में 10 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो ऐसे हैं, जहां कोई डॉक्टर नहीं हैं. इनमें से तो कई बिहार और उत्तर प्रदेश में होंगे. दूसरा, अस्पतालों में बेड की बहुत कमी है. ग्रामीण इलाकों में प्रति 10,000 की आबादी पर मात्र साढ़े तीन बेड ही उपलब्ध हैं, जबकि डब्ल्यूएचओ के अनुसार, प्रति 300 पर एक बेड होना चाहिए. तीसरी बात, ग्रामीण इलाकों में 20 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जिन्हें डॉक्टर कहा जाता है, लेकिन वे क्वालीफाइड नहीं हैं. चौथी समस्या है दूरी और परिवहन की. अगर कोई बीमार पड़ जाये, तो

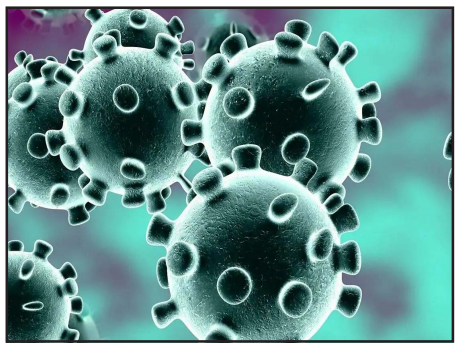

अस्पताल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों या जिला अस्पतालों तक मरीजों को पहुंचने में काफी समय लगता है. अंतिम महत्वपूर्ण बात, जागरूकता का बहुत अभाव है. बीमारी होने पर क्या करना है, यह उन्हें पता नहीं है. अब संक्रमण गांवों में तेजी से फैल रहा है और उसे नियंत्रित करने की जरूरत है. प्रवासी श्रमिकों के घर लौटने और अर्थव्यवस्था को खोलने से संक्रमण बढ़ा है.

अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक बंद नहीं रखा जा सकता, हरेक को अपना जीवन चलाना है. लेकिन, ध्यान रखना है कि बाहर निकलते समय विशेष एहतियात बरतें. कुछ राज्यों में संक्रमण की दर कम होने की खबर है. लेकिन, वहां जांच कैसे और किस तरह से की जा रही है, यह भी जानना जरूरी है. इम्युनिटी को लेकर अभी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है. कुछ देशों में इससे संबंधित कुछ रिसर्च हुई है. उससे स्पष्ट है कि संक्रमण के बाद में शरीर में जो एंटीबॉडीज बनते हैं, वे चार से पांच महीने तक रहते हैं. लेकिन, ये एंटीबॉडीज कितना सुरक्षा देते हैं, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. हालांकि, एंटीबॉडीज से थोड़ा बहुत अंतर जो जरूर आता होगा. अगर कहीं टेस्टिंग कम होगी, तो नंबर अपने आप ही कम हो जायेंगे. हमें देखना चाहिए कितने टेस्ट के बाद पॉजिटिव मामले दर्ज हो रहे हैं. केवल आंकड़ों को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि उचित रूप से टेस्टिंग हो रही है या नहीं. अच्छी दशा उसे कहा जाता है, जब आप ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करें और उसके अनुपात में पॉजिटिव मामलों की संख्या कम से कम दर्ज हो. क्या ये आरटीपीसीआर कर रहे हैं या रैपिड एंटीजन कर रहे हैं. रैपिड एंटीजन में गलत मामले दर्ज होने की संभावना अधिक रहती है. आरटीपीसीआर अपेक्षाकृत महंगी और जटिल टेस्ट विधा है. इसके लिए आपको एक्सपर्ट और इक्विपमेंट की जरूरत होती है. ज्यादातर मामलों में लोग रैपिड टेस्ट कर रहे हैं. इससे मामले की यथार्थ स्थिति का आकलन नहीं हो पाता. टेस्ट किये गये मामलों में अगर पॉजिटिव मामलों की संख्या से भाग करें, तो उससे पता चलेगा कि कितने टेस्ट करने पर संक्रमण का मामला दर्ज हो रहा है. अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है और पहली बार इस मौसम में हमें संक्रमण का सामना करना है. दूसरे देशों का उदाहरण देखें, तो जहां ठंड है, वहां कोविड के मामले बढ़े हैं, लेकिन वहां गंभीर मामले अधिक नहीं थे और मार्च-अप्रैल की तुलना में मौतों की संख्या कम रही, लेकिन इतना स्पष्ट है कि जब हम दरवाजे बंद करके सारे लोग एक जगह अंगीठी के आसपास बैठेंगे, तो वहां खुली हवा नहीं होगी, जिससे संक्रमण फैलने की गुंजाइश अधिक रहेगी. खासकर उत्तर भारत में ठंडक के मौसम में मामले बढ़ने की आशंका अधिक रहेगी. कई देशों में रिसर्च से पता चला है कि हर्ड इम्युनिटी नहीं बनती है. तीन प्रतिशत, पांच प्रतिशत या 10 प्रतिशत ही एंटीबॉडीज का प्रिविलेंस है. हर्ड इम्युनिटी के लिए यह आंकड़ा 65 से 70 प्रतिशत तक आना चाहिए. वह कहीं पर भी नहीं है.

अभी हमें मास्क पहनने और हाथ साफरखने की आदत डालनी होगी. मास्क अच्छी क्वालिटी का, और कम से कम तीन परत का होना चाहिए. मास्क को ढंग से पहनना होता है. पूरी तरह से नाक और मुंह ढंका होना चाहिए. शारीरिक दूरी बनाकर रखें और किसी चीज को छूने से बचें. अगर बीमार हो जाते हैं या बुखार आ रहा है, तो घर से बाहर न निकलें. त्योहारों का सीजन आ रहा है, अगर इस समय एहतियात नहीं बरते, तो हम संक्रमित हो सकते हैं. अभी स्कूल और सिनेमाघर आदि खोलने की फैसले किये गये हैं. बच्चे सावधानी बरतें, इसके लिए परिजनों को सतर्क रहने की जरूरत है. बच्चे फेस मास्क को आपस में बदल लेते हैं, इससे स्वस्थ्य बच्चा भी संक्रमित हो सकता है. बच्चों को एहतियात बरतना सिखाना होगा. अब हमें इस परिस्थिति के अनुसार ढलने की जरूरत हैं, साथ ही हर वक्त सावधान भी रहना है.

कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन

श्री प्रकाश सिंह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर जन आंदोलन अभियान की शुरुआत की. यह एक सोचा-समझा और सकारात्मक कदम है. हमारा देश कोरोना संकट से लड़ने को प्रतिबद्ध रहे, उसे लेकर ढिलाई न बरते, इस बात के लिए एक बार फिर से उन्होंने लोगों को आगाह किया है. सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति में भी प्रधानमंत्री मोदी को जितना ट्विटर, सोशल मीडिया पर फॉलो किया जाता है, उतना किसी दूसरे राष्ट्र के नेता को फॉलो नहीं किया जाता. यही कारण है कि प्रधानमंत्री द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है, वह बहुत महत्व रखता है.जहां तक कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या का प्रश्न है, तो बड़ी आबादी होने के बावजूद अब भी हमारी स्थिति तमाम राष्ट्रों से बेहतर है. हमारे यहां मृत्युदर बहुत कम है, संक्रमितों के ठीक होने की संख्या बढ़ी है, कंटेनमेंट जोन में कमी आने लगी है, लेकिन इन सब के बावजूद हम तब तक आश्वस्त नहीं हो सकते, जब तक हमारे पास इस बीमारी का कोई उपचार उपलब्ध नहीं हो जाता है. जब तक इसका कोई टीका हमारे पास नहीं आ जाता है. इन बातों को सोचते-समझते हुए ही प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर श्जन आंदोलन अभियान की शुरुआत की है. वे जानते हैं कि अभी हमें कोविड से लड़ने और इस लड़ाई में निरंतरता बनाये रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब लोग घरों से बाहर निकलना शुरू करते हैं, तो अपने व्यावहारिक जीवन में कहीं न कहीं कुछ मानकों की उपेक्षा करने लगते है. कोविड काल में जो लोग सड़कों पर, बाजारों में कम-से-कम दिख रहे थे, वह संख्या अब लगातार बढ़ रही है. ट्रैफिक भी सामान्य होता दिख रहा है. अब पूरा देश सामान्यीकरण की प्रक्रिया में जा रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये सुझाव, संदेश और उनका नेतृत्व प्रशंसनीय है. प्रधानमंत्री के इस अभियान का मकसद एक बार फिर से लोगों को रोकथाम व बचाव के उपायों की तरफले जाना हैं, ताकि वे आपदा से बचे रहें. हमारे पास अभी इस बीमारी के उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है जहां तक इस अभियान के प्रभाव की बात है, तो प्रधानमंत्री ने जब-जब राष्ट्र को संबोधित किया है, भले ही उनका माध्यम कोई भी रहा हो, पूरे देश ने उनकी बात सुनी है और उसे माना है. यह एक तरह से जागरूकता अभियान ही हैष्. प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व द्वारा जब कोई बात कही जाती है, तो समाज के तमाम लोग उससे प्रभावित होते हैं और यदि उन्होंने थोड़ी ढिलाई बरतनी शुरू की थी, तो वे वापस संभल जायेंगे.संक्रमण से बचाव को लेकर जिनके ध्यान में थोड़ी कमी आयी थी, वो पुनरू ध्यान रखना शुरू कर देंगे. प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये इस अभियान का बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़नेवाला है. एक तरह से प्रधानमंत्री ने जनता को यह बताने का भी प्रयास किया है कि आप लापरवाह न हों, क्योंकि समस्या अभी बदस्तूर बनी हुई है, संक्रमितों की संख्या भी बढ़ रही है. इसलिए आनेवाले समय में भी इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है. कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री ने लगातार अगुआई की है और जनता से संवाद बनाये रखा है. पूरी दुनिया के साथ भारत सरकार और उसका नेतृत्व भी कोरोना के टीके को विकसित करने के लिए प्रयारसत है. लॉकडाउन लगाने, लोगों को अनुशासित करने और जागरूकता फैलाने के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा जो भी कदम उठाये गये थे, वे सभी बहुत लाभकारी सिद्ध हुए हैं. सिंगापुर एमआइटी के शोध ने तो शुरुआत में ही यह बात कह दी थी कि यदि भारत में लॉकडाउन नहीं लगाया गया होता, तो संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती. लॉकडाउन का असर हुआ और संक्रमण के चक्र को तोड़ने में हमें सफलता मिली. जिस तेजी से वह बढ़ रहा था, कहीं न कहीं उसे रोकने में भी सफलता मिली. चूंकि, अर्थव्यवस्था की अपनी जरूरत है, इसलिए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गयी. इस प्रक्रिया के दौरान जब कुछेक औद्योगिक इकाइयों को फिर से खोला गया, आवागमन को पुन सुचारु बनाया गया, ऐसे में लोगों का एक-दूसरे से संपर्क बढ़ा इस कारण संक्रमण के मामले भी बढ़ते गये. चूंकि, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यूरोपीय देशों की तुलना में बेहतर है, ऐसे में तमाम लोग संक्रमित हुए और ठीक हो गये. जिस तरह के एहतियाती उपाय हमारे यहां किये गये, उसका लाभ हुआ है. इस अभियान के जरिये प्रधानमंत्री ने हमें यह याद दिलाया है कि इस बदलते मौसम में तमाम वायरस सक्रिय हो जाते हैं, ऐसे में यह वायरस भी ज्यादा सक्रिय हो सकता है, इसलिए रोकथाम के उपायों को लेकर किसी तरह की कोताही ना बरती जाये. शोधार्थियों ने भी सर्दियों में संक्रमण के बढ़ने को लेकर संभावना जतायी है. इसे देखते हुए ही प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से देशवासियों को इस ओर ध्यान दिलाने का प्रयास किया है कि हम अभी आश्वस्त न हो जायें कि यह समस्या खत्म हो चुकी है, बल्कि समस्या अभी अपनी जगह बनी हुई है. इस नाते अभी भी हमको पूरी सावधानी बरतनी है। सोशल मीडिया के जो तमाम माध्यम हैं, उनके जरिये कई बार बहुत छोटा संदेश भी बहुत बड़ी बात कह रहा होता है. ट्विटर के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा संदेश इसलिए दिया गया है, क्योंकि ट्विटर बहुत तेजी से काम करता है और वहां पोस्ट किये गये संदेश को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया बहुत तेजी से उठाते हैं. वहां प्रतिक्रियाएं भी त्वरित होती हैं. हम सहमत होते हैं तो उसको लाइक और रिट्वीट करते हैं. कई बार रिट्वीट के माध्यम से हम अपनी बात भी कह रहे होते हैं. एक तरह से ट्विटर लोगों में जागरूकता फैलाने और उन तक अपनी बात पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है. इसी कारण प्रधानमंत्री समय-समय पर अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, इस माध्यम को चुनते हैष्. भले ही हमारे देश की बहुत सी जनता ट्विटर पर नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से यह बात जन-जन तक पहुंचेगी. प्रधानमंत्री जब कोई बात करते हैं, तो सभी मीडिया हाउसेज उसको प्रमुखता से रखते हैं. इतना ही नहीं, जब कोई विषय विमर्श में आ जाता है, तो उसका प्रभाव समाज पर पड़ता ही है. मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री ने एकदम सही माध्यम का चुनाव किया है, क्योंकि समस्या बरकरार है, भले ही इसका स्वरूप बदला है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था का नया दौर

डॉ. जयंती लाल भंडारी

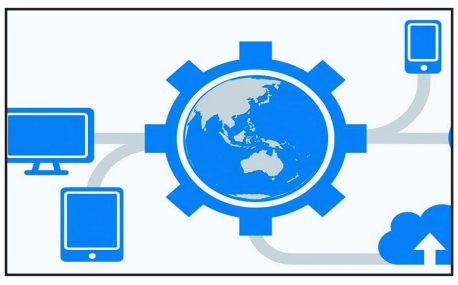

आर्टिफिशियल इंटेलिजेस (एआइ) पर पांच दिवसीय वैश्विक डिजिटल शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कृषि, शिक्षा, शहरी बुनियादी अधोसंचरना और आपदा प्रबंधन के तंत्र को मजबूत करने के लिए एआइ को प्रभावी बनाया जाना जरूरी है. भारत में एआइ की उपयोगिता बढ़ाकर आर्थिक और सामाजिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है. देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था के तहत विदेशी निवेश आने का सुकूनभरा परिदृश्य उभर रहा है. कोरोना महामारी के बीच डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए अप्रैल से जुलाई, 2020 के बीच 16.26 अरब डॉलर का एफ्डीआइ आया है. अमेरिकी टेक कंपनियां भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा रिटेल के इ-कॉमर्स बाजार में निवेश कर रही हैं. वस्तुत: देश के डिजिटल क्षेत्र में विदेशी निवेश के पीछे कई कारण हैं. लॉकडाउन में ऑनलाइन एजुकेशन तथा वर्क फ्रॉम होम, इंटरनेट के बढ़ते उपयोगकर्ता, सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण, जनधन खातों में लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से भुगतान, प्रति व्यक्ति डेटा खपत तथा मोबाइल ब्रॉडबैंड ग्राहकों की तादाद बढ़ना प्रमुख कारण हैं. डिजिटल भुगतान उद्योग, इ-कॉमर्स तथा डिजिटल मार्केटिंग जैसे सेक्टर तेजी से उभर रहे हैं. देशभर में डिजिटल भुगतान की स्वीकार्यता स्वेच्छा से बढ़ी है. लॉकडाउन के कारण घरों पर रहते हुए लोगों ने इ-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग को जीवन का अंग बना लिया. अब अनलॉक में भी लोग भीड़भाड़ से बचने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। जैसे-जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था डिजिटल हो रही है, वैसे-वैसे रोजगार बाजार का परिदृश्य बदल रहा है. स्थिति यह है कि भविष्य में कई रोजगार ऐसे भी होंगे, जिनके नाम हमने अब तक सुने भी नहीं हैं. ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते जहां कई क्षेत्रों में रोजगार कम हो रहे हैं, वहीं डिजिटल अर्थव्यवस्था में रोजगार बढ़ रहे हैं. इस क्षेत्र में भारतीय प्रतिभाओं के लिए मौके केवल देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया के कोने-कोने में भी होंगे. कुछ समय पहले विश्व बैंक सहित कुछ संगठनों ने वैश्विक रोजगार से संबंधित रिपोर्टों में कहा है कि आगामी 5-10 वर्षों में, जहां दुनिया में कुशल श्रमबल का संकट होगा, वहीं भारत के पास कुशल श्रमबल अतिरिक्त संख्या में होगा. ऐसे में भारत कई विकसित और विकासशील देशों में कुशल श्रमबल भेजकर फायदा उठा सकेगा. सरकार ने डिजिटलीकरण के उद्देश्य से नीतिगत स्तर पर कई सराहनीय कदम उठाये हैं, लेकिन अभी इस दिशा में बहुआयामी प्रयासों की जरूरत है. अभी बुनियादी जरूरतों से संबंधित कमियों को दूर करना है. ग्रामीण आबादी का एक बड़ा भाग अभी भी डिजिटल रूप से अशिक्षित है. अतएव, ग्रामीणों को इसके लिए शिक्षित-प्रशिक्षित करना होगा. चूंकि, बिजली डिजिटल अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण जरूरत हैं, अतरू ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की पर्याप्त पहुंच होनी चाहिए. अभी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास डिजिटल पेमेंट के तरीकों से भुगतान के लिए बैंक-खाता, इंटरनेट की सुविधा युक्त मोबाइल फोन या क्रेडिट-डेबिट कार्ड की सुविधा नहीं है. अतरू ऐसी सुविधाएं बढ़ाने का जोर देना होगा. चूंकि, डिजिटल भुगतान के समय होनेवाली ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाओं के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीणों का ऑनलाइन लेनदेन में अविश्वास बना हुआ है, अतएव इसके लिए सरकार को साइबर सुरक्षा मजबूत करनी होगी. डिजिटलीकरण के लिए मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड बढ़ाना जरूरी है. मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड टेस्ट करनेवाली वैश्विक कंपनी ओकला के मुताबिक अप्रैल, 2020 में मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में 139 देशों की सूची में भारत 132वें पायदान पर है. ऐसे में, भारत को रोजगार के मौकों का फायदा लेने के लिए मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड को बढ़ाने के अधिकतम प्रयास करने होंगे. अभी सीमित संख्या में ही कौशल प्रशिक्षित प्रतिभाएं डिजिटल अर्थव्यवस्था की रोजगार जरूरतों को पूरा कर पा रही हैं. अब दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी वाले भारत में युवाओं को डिजिटल दौर की तथा नयी तकनीकी रोजगार योग्यताओं से सुसज्जित करना होगा. डिजिटल दुनिया में करियर बनाने के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था की विशेषज्ञता के साथ अच्छी अंग्रेजी, कंप्यूटर दक्षता, कम्युनिकेशन स्किल, जनसंचार तथा विज्ञापन क्षेत्र से जुड़ी हुई स्किल्स लाभप्रद होती हैं. तकनीकी कुशलता के संदर्भ में वेब डिजाइन, सोशल मीडिया, वेब संबंधित सॉफ्टवेयर का अच्छा ज्ञान, विश्लेषणात्मक कौशल और अनुसंधान कौशल भी लाभप्रद होता है. नयी शिक्षा नीति में जिस तरह डिजिटल दुनिया के नये दौर के कौशल विकास पर काफी जोर दिया गया है, उसके प्रभावी क्रियान्वयन से देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था में रोजगार के मौके बढ़ेंगे. हम उम्मीद करें कि देश की नयी पीढ़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था के पीछे छिपे हुए अवसरों को तलाशेगी और देश एवं दुनिया की नयी जरूरतों के मुताबिक अपने को सुसज्जित करेगी. निश्चित रूप से भारतीय प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल अर्थव्यवस्था में निर्मित होनेवाले मौकों को अपनी मुठ्ठियों में लेते हुए दिखायी दे सकेंगी.

किसानी के प्रतिकूल हैं, हाल में बने कानून

राजगोपाल पी.

सरकार ने हाल में खेती-किसानी से जुड़े तीन कानून पारित करवाए हैं। उनको लेकर किसानों के बीच आक्रोश तो है ही, किसान, आदिवासी और मछुआरा समुदाय के साथ काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं के मन में भी आक्रोश है। नतीजतन देश भर में एक आंदोलन का माहौल बनता जा रहा है। ऐसे में इन कानूनों को जल्द-से-जल्द वापस लेने में ही सरकार की बुद्धिमानी होगी। किसानों के संदर्भ में कोई निर्णय लेना जरूरी हो तो भी किसानों के साथ परिचर्चा कर उनकी अभिलाषाओं के अनुकूल नियम-कानून बनाना चाहिए था। सलाह, परिचर्चा और व्यापक संवाद के बिना जो कानून बनाए गए हैं और उनके माध्यम से देश भर की कृषि को चलाने की जो कोशिशें हो रही हैं, उससे लोकतंत्र को भी खतरा है। यदि खेती-किसानी के लिये कानून बनाना बहुत जरुरी हो तो भी सरकार को पहले एमएस स्वामीनाथन कमीशन का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और कर्जमाफी के सुझाव को लागू करना चाहिये था। उसके बाद बाकी बातों पर सरकार को चर्चा शुरू करना चाहिए थी। यह नहीं करने से जाहिर होता है कि सरकार को जो करना चाहिए, वह नहीं कर रही और जो नहीं करना चाहिए वह कर रही है। यह कोई प्रजातांत्रिक तरीका नहीं है। देश भर में मंडियों का गठन इसलिए हुआ था कि किसान को स्वाभिमान से जीने के लिए उनकी एक संस्थागत व्यवस्था कायम हो सके, ताकि किसान को भी लगे कि हमारे संरक्षण के लिए कोई संस्था है। खुले बाजार में बाजार की ही शर्तों पर बेचने और ताकतवर लोगों के सामने हाथ फैलाकर खड़े रहने के खिलाफऔर इस व्यवस्था को बदलने के लिए ही तो मंडी व्यवस्था कायम की गई थी। उस मंडी व्यवस्था को समाप्त करना कोई बुद्धिमता नहीं है। इसी तरह संविदा खेती (कांट्रेक्ट फार्मिंग) की बात की जा रही है। हम सब जानते हैं कि यह संविदा खेती कितनी खतरनाक है। हमने कोयले का व्यापार कर लिया, अन्य खनिजों का व्यापार कर लिया, पानी का व्यापार कर लिया और अब खेती का व्यापार करने जा रहे हैं। संविदा खेती में ताकतवर लोग आएंगे। खेती पर स्वाभिमानी ढंग से जीवनयापन करते साधारण किसानों को ताकतवर बनाने के बदले उनको संविदा खेती के तहत कमजोर करने की जो प्रक्रिया है, वह सही नहीं है। कोविड के दौरान प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि मैं इस देश को स्वावलंबी बनाना चाहता हूं। ऐसा स्वावलंबी समाज गांव से ही तो बनेगा। जल, जंगल और जमीन पर यदि लोगों का अधिकार नहीं है, जीवन जीने का निर्णय लेने का अधिकार उन लोगों को नहीं है तो स्वावलंबी समाज की रचना कैसे होगी ? इसमें समन्वय की कमी झलकती है। एक तरफ हम स्वावलंबी समाज बनाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफआप जो कर रहे हैं वह इसके बिल्कुल विपरीत है। सन् 2012 में बड़े आंदोलन के बाद, जहां एक लाख लोगों को लेकर एकता परिषद और उसके सहयोगी संगठनों ने दिल्ली की ओर कूच किया तो 2013 में श्भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम कानून लाने में हम सफल हुए थे। इस कानून में यह कोशिश की गई है कि जैसे भूमि-अधिग्रहण के मामले में अच्छी भूमि उद्योग के लिए नहीं देने की बात है।

शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होने देगी ये चीज

कैल्शियम जो हर किसी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो तत्व है जो हड्डियों को मजबूती देता है। महिलाओं और बच्चों के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए जहां यह विकास के लिए जरूरी होता है, वहीं महिलाओं के लिए यह इसलिए जरूरी है क्योंकि पीरियड्स, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज के समय शरीर में कैल्शियम की खपत बढ़ जाती है, जिसके चलते कैल्शियम की कमी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। खासकर 30 के बाद महिलाओं के शरीर में इसकी कमी होने लगती है इसलिए इस और ध्यान देना जरूरी हो जाता है लेकिन भारतीय औरतें इसको लेकर लापरवाही बरतती है जबकि ऐसा कर वह खुद स्वस्थ संबंधी परेशानियों को खुद ही न्योता दे देती हैं। कैल्शियम की कमी के चलते ही जोड़ों में दर्द रहने लगता है। इससे दांत भी कमजोर होने लगते है वहीं अगर समस्या बढ़ जाए तो गठिए होने के चांस भी बढ़ जाते हैं।

हड्डियों के लिए जरूरी है कैल्शियम

हड्डियों का 70: हिस्सा कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। यही कारण है कि कैल्शियम हमारी हड्डियों की अच्छी सेहत के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है।

किन महिलाओं को अधिक होती है समस्या

रिसर्च के अनुसार, 14 से 17 साल तक

की लगभग 20: लड़कियों में कैल्शियम की कमी पाई जाती हैं। वहीं इससे ज्यादा उम्र वाली महिलाओं में लगभग 40-60: तक कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है। दरअसल, पीरियड्स, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज के समय शरीर में कैल्शियम की खपत बढ़ जाती है। यही कारण है कि महिलाओं में कैल्शियम की कमी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है।

कैल्शियम की कितनी मात्रा है जरूरी

पुरुषों के मुकाबले, महिलाओं को 30 की उम्र के बाद कैल्शियम की जरूरत ज्यादा होती है। भारत में लोग हर दिन 400 ग्राम से कम कैल्शियम खाते हैं, खासतौर पर औरतें जबकि शरीर को 1200-1500 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए होता है।

दूध पिलाने वाली मांओं को अधिक जरूरत प्रेगनेंट और स्तनपान करवाने वाली औरतों को न्यूटिशियंस और कैल्शियम से भरपूर आहार खाने की बहुत जरूरत होती है क्योंकि गर्भवती और बच्चे को दूध पिलाने वाली मां के शरीर से ही बच्चा का पूर्ण पोषण होता है इसलिए इन महिलाओं को दूसरी औरतों के मुकाबले कैल्शियम की भी ज्यादा जरूरत होती है।चलिए अब जानते हैं कि आखिर इसके कारण क्या है...

-कैल्शियम की कमी की एक बड़ी वजह है डाइट। भारतीय महिलाएं अपने खान-पान को लेकर लापरवाह होती है, जो इसकी कमी का कारण बनता है।

-मेनोपॉज के दौरान महिलाओं को खासतौर पर ज्यादा कैल्शियम खाना चाहिए क्योंकि इस दौरान एस्ट्रोजेन हॉर्मोन का स्तर कम हो जाता है, जिससे हड्डियां पतली होने लगती हैं

-आमतौर पर लड़कियों को वैजाइनल डिस्चार्ज होता है। ये नॉर्मल है लेकिन इसमें कैल्शियम भी निकलता है। वहीं इस डिस्चार्ज में सोडियम, पोटेशियम, और मैग्नीशियम भी होता है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि आप अपनी डाइट पर ध्यान दें।

अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही हैं तो यह संकेत दिखाई देंगे...

. हड्डियां कमजोर होना
. दांतो में कमजोरी
. नाखून कमजोर होना
. पीरियड्स से जुड़ी प्रॉब्लम्स
. बालों का झड़ना
. थकावट महसूस करना
. कमजोर इम्यून सिस्टम
. धड़कन तेज होना

कुछ जरूरी बातें

-जिन औरतों में कैल्शियम की कमी होती है, उनकी हड्डियां काफी कमजोर हो जाती हैं। -40 की से ऊपर या जिन महिलाओं को मेनोपॉज हो चुका हो उनका शरीर कैल्शियम कम मात्रा में सोखता है।

-जो औरतें केवल शाकाहारी खाना खाती हैं उनमें कैल्शियम की ज्यादा देखने को मिलती है।

-16 से 30 साल की लड़कियां जो डाइटिंग करती हैं, उनमें कैल्शियम की कमी होने की संभावना अधिक होती है।

-शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर भी कैल्शियम कम हो जाता है क्योंकि यह कैल्शियम सोखने में मदद करता है।

कैल्शियम की कमी से क्या-क्या दिक्कतें हो सकती हैं...

. ऑस्टियोपोरोसिस
. ऑस्टियोपीनिया
. हाईपोकैल्शिमिया

कैल्शियम के लिए क्या खाएं

कैल्शियम के लिए मार्कीट में आपको अच्छे सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे लेकिन अगर आप कैल्शियम भरपूर डाइट खाएं तो ज्यादा फायदेमंद है। दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की भरमार होती है। वहीं, बात आए कैल्शियम की, तो दूध का नाम सबसे पहले आता है इसके अलावा दही व पनीर भी खाएं।.

डेंगू से बचाव के लिए अपनाएं यह आसान उपाय

डेंगू बुखार एक फ्लू जैसी बीमारी है, जो डेंगू वायरस के कारण होती है। यह तब होता है, जब वायरस वाला एडीज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है। भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिणी चीन, ताइवान, मैक्सिको और मध्य अमेरिका जैसे कई उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह बुखार हर साल होता है।

हर साल लगभग 500,000 लोग इस बीमारी से प्रभावित होते हैं और मृत्यु दर 2.5 प्रतिशत होती है। जब कोई व्यक्ति मच्छर से संक्रमित होता है, तो वायरस रक्त में 2-7 दिनों के लिए फैलता है।

डेंगू की बीमारी होने पर व्यक्ति को सिरदर्द, हड्डी व जोड़ों में दर्द, जी मचलाना, उल्टी आना, त्वचा पर लाल चकत्ते होना जैसे लक्षण नजर आते हैं। इस बुखार से बचाव के लिए आप स्वयं ही कुछ कदम उठा सकते हैं। जो हम आपको इस लेख में बता रहे हैं-

त्वचा को ढककर रखें

हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि अभी डेंगू के लिए कोई विशिष्ट दवा उपलब्ध नहीं है।

ऐसे में डेंगू से बचाव ही सबसे उत्तम उपाय है। इसके लिए आप अपनी स्किन को ढककर रखें। इससे मच्छर के काटने की संभावना काफी कम हो जाती है।

आप कोशिश करें कि पूरी बाजू की शर्ट व टीशर्ट व लंबी पैंट पहनें। इसके अलावा, डेंगू के मच्छर सुबह व शाम को अत्यधिक सक्रिय होते हैं, इसलिए जहां तक हो सके, इस समय बाहर जाने से बचें।

क्रीम का करें इस्तेमाल

हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, ऐसी क्रीम का इस्तेमाल करें, जो मच्छरों का आपसे दूर रखें। आप हर दिन इस क्रीम का इस्तेमाल करें। अगर आपकी स्किन सेंसेटिव है तो ऐसे में मच्छर को भगाने के लिए मॉस्किटो पैच या रोल-ऑन आदि का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। **व्यक्तिगत स्वच्छता का रखें ख्याल**

आपको कोई भी वायरस संक्रमित ना कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि आप व्यक्तिगत स्वच्छता का ख्याल रखें। कीटाणुओं को खुद से दूर रखने के लिए हाईजीन व साफ-सफाई का पूरी तरह ख्याल रखें।

पानी का प्रबंधन

ठहरे हुए पानी में अक्सर डेंगू के मच्छर पनपते हैं, इसलिए पानी का सही तरह से प्रबंधन करना बेहद जरूरी है। घर में मौजूद खाली बाल्टियों को पलट दें ताकि उनमें पानी इकट्ठा ना हो सके। पानी के भंडारण के लिए उपयोग की जाने वाली बाल्टियाँ और ड्रमों को ढक कर रखें। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि आपके प्लांटर में ओवर वाटरिंग ना हो।

टूटे हुए सेप्टिक टैंकों की मरम्मत करें और यदि कोई टूटा हुआ हो तो तार की जाली के साथ वेंट पाइप को कवर करें।

यदि आपके पास घर पर कूलर है, तो सुनिश्चित करें कि आप इसे नियमित रूप से साफकरते हैं। डस्टबिन को साफरखेंय मच्छरों से बचने के लिए किसी भी गंदगी को इकट्ठा न होने दें।

रखें इसका ख्याल

कपूर को घर में जरूर जलाएं, यह मच्छरों को दूर रखने में मदद करेगा। साथ ही मच्छरदानी के नीचे सोएं।

मेनोपॉज के बाद हार्मोन को बैलेंस में रखते हैं ये 4 योगासन

50-55 के बाद महिलाओं को पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, जिसे मेनोपॉज भी कहा जाता है। यह कोई बीमारी नहीं बल्कि नैचुरल प्रोसेस है, जो महिला में होता है। हालांकि, इसके बाद महिलाओं को हार्मोनल असंतुलित जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

साथ ही मेनोपॉज के बाद महिलाओं में दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में आज हम आपको कुछ योगासनों के बारे में बताएंगे, जो मेनोपॉज के बाद हार्मोन्स को संतुलित रखने के साथ-साथ दिल की बीमारियों का खतरा भी कम करेंगे।चलिए जानते हैं रजोनिवृत्ति यानि मेनोपॉज के बाद आपको कौन-कौन से आसन करने चाहिए...

सुखासन

इससे न सिर्फ मेनोपॉज के लक्षण कम होते हैं बल्कि यह आपको स्ट्रेस फ्री रखने में भी मदद करता है।

साथ ही इससे मांसपेशियों में भी मजबूती आती है और आपको जोड़ों में दर्द की समस्या नहीं होती।

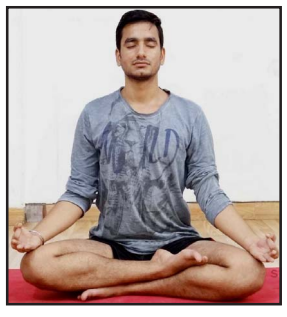

योग करने का तरीका

इस आसन को करने के लिए पालती मारकर बैठ जाएं। फिर अपनी पीठ सीधी रखें और आंखें बंद करें। इसके बाद अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पर रखकर 3-4 गहरी सांस अंदर व बाहर लें।

ताड़ासन

इससे मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जिससे दर्द व सूजन की समस्या कम होता है। साथ ही यह पेट और श्रोणि क्षेत्र को मजबूत करता है, जिससे मेनोपॉज के लक्षण कम होते हैं। इसके अलावा इससे हार्मोन्स भी बैलेंस

रहते हैं।

योग करने का तरीका

इसके लिए आप अपने पैरों को एक साथ जोड़कर सीधे खड़े हो जाए। अब अपने हाथों को ऊपर की तरफ सीधा उठाएं और गहरी सांस लेते हुए आंखें बंद करें। अब धीरे-धीरे सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं।

उत्तानासन

इससे न सिर्फ मेनोपॉज के लक्षण कम होते हैं बल्कि यह हार्मोन्स को भी संतुलन में रखता है। साथ ही यह योग दिल की बीमारियों का खतरा भी कम करता है।

योग करने का तरीका

इस योग को करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं। फिर सांस लेते हुए अपने अपर बॉडी पार्ट को झुकाएं और पैर की उंगलियों को छूने की कोशिश करें। कुछ देर इस स्थिति में रूके लेकिन ध्याकन रहे कि आपके घुटने सीधे हो। फिर सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापिस आ जाए।

सलंब सर्वांगासन

मेनोपॉज के कारण डिप्रेशन से गुजर रही महिलाओं के लिए यह आसन बेहद फायदेमंद है। साथ ही यह शरीर में हार्मोनल परिवर्तन

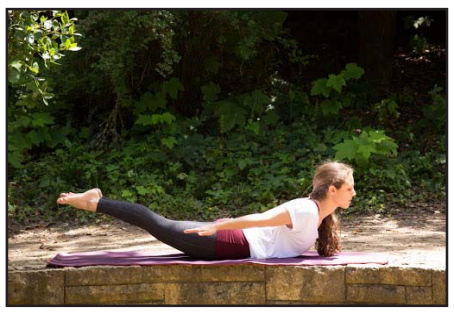

के कारण मूड स्विंग को कम करने में भी काफी मददगार है।

योग करने का तरीका

सिर के नीचे एक मुड़ा हुआ कंबल या पतला तकिया रखकर जमीन पर लेटे। अब सांस लेते हुए कंधों के सहारे अपने शरीर के निचले हिस्सेत यानि कमर और पैरों को जमीन से ऊपर उठाएं। पैरों को इस तरह ऊपर उठाए कि आपके घुटने चेहरे के ठीक सामने हो। अपनी कोहनी को आरामदायक स्थिति में रखें। धीरे-धीरे सांस लेते रहें और कुछ देर बाद सामान्य स्थिति में आ जाए।

दिल्ली में इन जगहों का लुत्फ उठाने के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे

जामा मस्जिद, जिसे मस्जिद ई जहान नुमा के नाम से भी जाना जाता है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। यह मुगल सम्राट शाहजहाँ द्वारा बनाया गया था और इसका उद्घाटन इमाम सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी ने किया था। दिल्ली देश की राजधानी है और पर्यटक इसे देश का दिल मानते हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि दिल्ली में खाने-पीने से लेकर घूमने तक के लिए कई बेहतरीन जगहें मौजूद हैं। इतना ही नहीं, यहां पर हर तरह के व्यक्ति के लिए घूमने और देखने के लिए कुछ ना कुछ है। आमतौर पर जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली में हैं तो आपको इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी हां, दिल्ली की ऐसी कई बेहतरीन जगहें हैं, जो पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र हैं, लेकिन यहां पर घूमने के लिए आपको पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ बेहतरीन जगहों के बारे में-

घूमें जामा मस्जिद

जामा मस्जिद, जिसे मस्जिद ई जहान नुमा के नाम से भी जाना जाता है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। यह मुगल सम्राट शाहजहाँ द्वारा बनाया गया था और इसका उद्घाटन इमाम सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी ने किया था। यहाँ तीन विशाल मुख्य द्वार हैं जो सभी चालीस मीटर ऊँचे हैं और निर्माण में सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर की पट्टियों के साथ मस्जिद के काम को खूबसूरती से दिखाया गया है। मस्जिद के यहाँ एक विशाल प्रांगण भी है। यह आंगन इतना विशाल है कि यहां लगभग 25,000 उपासक बैठ सकते हैं और यह 408 वर्ग फीट की जगह घेरता है। इस मस्जिद के आंगन में घूमना एक अद्भुत एहसास होता है।

हजरत निजामुद्दीन दरगाह में कव्वाली संगीत

हजरत निजामुद्दीन दरगाह में कव्वाली संगीत दिल्ली में मुफ्त में दिल्ली में करने के लिए चीजों का अनुभव करना चाहिए। यहां कव्वाली का प्रदर्शन पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर सकता है। यह शो हर दिन होता है। कुछ अद्भुत सूफी गीत जैसे भर दो झोली मेरी, कुन फाया कुन, छप तिलक सब छेनी, अज रंग है और कई अन्य यहां प्ले किए जाते हैं और इस तरह यहां एक सम्मोहित करने वाला वातावरण बनता है। निजामुद्दीन औलिया के वंशज, जिन्हें निजामी ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है, इस स्थान पर वास्तविकता के साथ-साथ प्रामाणिकता की भावना भी लाते हैं। नियाजमी ब्रदर्स का परिवार सात सौ से अधिक वर्षों से इस स्थान पर गा रहा है।

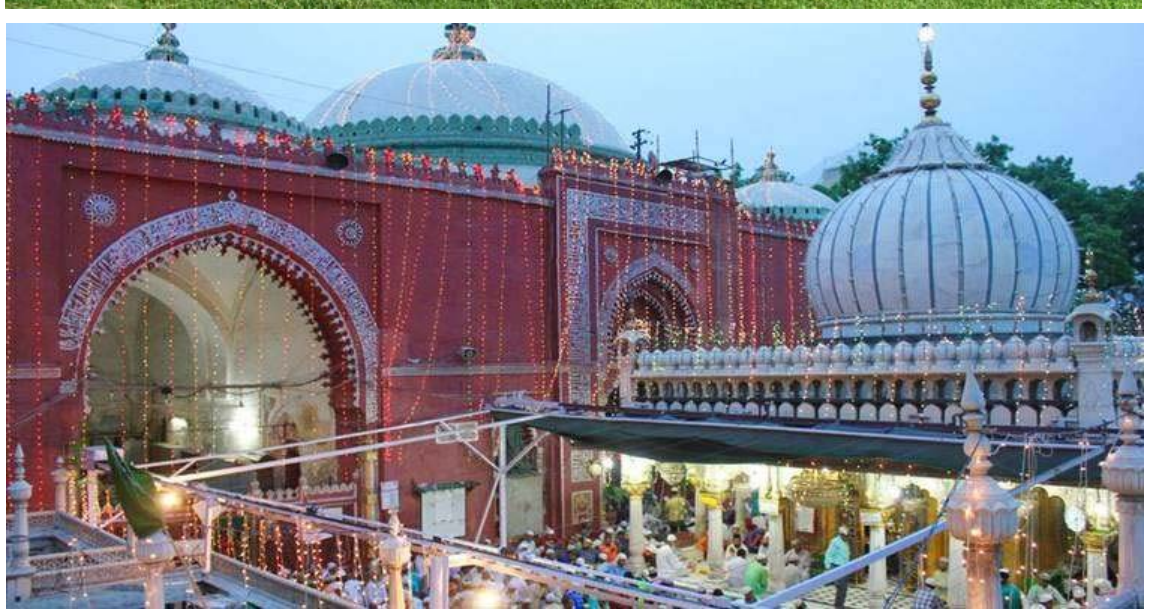

लोधी गार्डन

दिल्ली का लोधी गार्डन, दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक है। यह स्थान सभी फोटोग्राफी प्रेमियों, वास्तुकला प्रेमियों और उन सभी लोगों के लिए घूमने के लिए एक शानदार जगह है जो कुछ नया अनुभव करना चाहते हैं। यह स्थान सप्ताह के सभी दिनों में पर्यटकों के लिए खुला रहता है और दरवाजे सुबह 6 से शाम 7 बजे तक खोले जाते हैं। ताजा वातावरण और इस जगह में अद्भुत वास्तुकला के कारण लोधी उद्यान इस जगह पर आने वाले पर्यटकों के बीच प्रसिद्ध है। यह भी एक तथ्य है कि सैय्यद और लोधी वंश के शासक यहां दफन थे। यह जगह यहां पुराने वाटर टैंक की वजह से भी बेहद खूबसूरत है। लोधी गार्डन में भी बहुत सारी चीजें हैं जो यहां पर्यटकों को आकर्षित करती हैं।

जम्मू कश्मीर में बायोफ्लॉक तकनीक से होगा मत्स्यपालन, मछली पालन को मिलेगा बढ़ावा

(एजेंसी) जम्मू। जम्मू कश्मीर सरकार केंद्र शासित प्रदेश के संभावित क्षेत्रों में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए बायोफ्लॉक तकनीक (बीएफटी) की शुरुआत कर रही है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। मत्स्य, पशु-भेड़पालन, कृषि, बागवानी और सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव नवीन चौधरी ने कहा कि विभाग की योजना कृषक समुदाय और बेरोजगार युवाओं के बीच इस नयी तकनीक को बढ़ावा देने की है, ताकि उनके लिये आय का सृजन का स्रोत बन सके। बायोफ्लॉक को मत्स्यपालन में नयी नीली क्रांति माना जा रहा है। यह मछली पालन का एक लाभदायक तरीका है और यह पूरी दुनिया में खुले तालाब में मछली पालन का बहुत लोकप्रिय विकल्प बन गया है। यह एक कम लागत वाला तरीका है, जिसमें मछली के लिये विषाक्त पदार्थ जैसे अमोनिया, नाइट्रेट और नाइट्राइट को उनके भोजन में परिवर्तित किया जा सकता है। इस तकनीक का सिद्धांत पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करना है। चौधरी ने कहा, ''तालाब में मछली पालन के पारंपरिक तरीके के मुकाबले बायोफ्लॉक तकनीक के कई लाभों को देखते हुए तथा मछली पालकों को इसका उच्च उत्पादन दिखाने के लिये इसे प्रदेश में पेश किया जा रहा है।'' चौधरी ने हाल ही में कर्नल (सेवानिवृत्त) सुनील सिंह समब्याल द्वारा स्थापित बायोफ्लॉक यूनिट के निरीक्षण के लिये यहां मेलुरी जगिर बजल्ता में हंटर्स रेंच का दौरा किया। उन्होंने कहा कि यह तकनीक पहले ही कई राज्यों में अपनायी जा चुकी है और इकाइयां सफलतापूर्वक चल रही हैं। प्रमुख सचिव ने रोटेशन के आधार पर इस बायोफ्लॉक यूनिट में प्रशिक्षण के लिये सभी जिलों के कर्मचारियों को नियुक्त करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने हाल ही में पेश आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिये आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत मत्स्य पालन के टिकाऊ तरीके से नीली क्रांति लाना है।

जन औषधि केंद्र खोलकर सरकार से पा सकते हैं 2.5 लाख रुपये

(एजेंसी) अगर आप भी अपने शहर में जन औषधि केन्द्र खोलना चाहते हैं तो फिर देर किस बात की। जन औषधि केन्द्र खोलने की प्रक्रिया इतनी आसान है कि इसे घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इस योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना है। आइये कैसे खोल सकते हैं जन औषधि केन्द्र के बारे में जानने से पहले यह जान लें कि इसे खोलने से आपको क्या फायदा होगा... मोदी सरकार की प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना एक ऐसी योजना है, जिसके तहत न केवल रोजगार मिलाता है, बल्कि मरीजों को मार्केट रेट से काफी सस्ती दवाएं भी मिल जाती हैं। अभी देश में करीब 6000 जन औषधि केन्द्र चल रहे हैं, लेकिन अभी भी हजारों जन औषधि केन्द्र खोलने की योजना है। जन औषधि केन्द्र खोलने में ज्यादा खर्च भी नहीं आता है, जो भी खर्च आता है वह सरकार धीरे धीरे आपको वापस कर देती है। इसके अलावा हर महीने आपको अच्छा कमीशन मिलता है। सरकार जन औषधि केंद्र खोलने पर 2.5 लाख रुपये तक की मदद करती है। जन औषधि केंद्र से दवाओं की बिक्री से 20 फीसदी तक का मुनाफा मिलता है। इसके अलावा हर महीने होने वाली बिक्री पर अलग से 15 प्रतिशत का इंसेंटिव मिलता है, हालांकि इंसेंटिव की अधिकतम सीमा 10,000 रुपये महीना तय है। यह इंसेंटिव तब तक मिलेगा, जब तक कि 2.5 लाख रुपये पूरे न हो जाएं। वहीं नक्सल प्रभावित और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इंसेंटिव की अधिकतम सीमा 15 हजार रुपये प्रति माह तक है।

एक लाख रुपये की दवाइयां पहले आपको खरीदनी होगी

सेंटर शुरू करने पर 1 लाख रुपये की दवाइयां पहले आपको खरीदनी होगी। बाद में सरकार इसे रीइंबर्समेंट करेगी। इसके अलावा दुकान शुरू करने में रैक, डेस्क आदि बनवाने, फ्रीज खरीदने में सरकार आपको 1 लाख रुपये तक की सहायता करेगी। सेंटर खोलने के लिए कंप्यूटर आदि के सेटअप पर 50 हजार रुपये तक के खर्च पर भी सरकार यह पैसा रिटर्न करेगी।

कौन खोल सकता है

पहली कैटेगरी के तहत कोई भी व्यक्ति, बेरोजगार फार्मासिस्ट, डॉक्टर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जन औषधि केंद्र खोल सकता है। दूसरी कैटेगरी के तहत ट्रस्ट, एनजीओ, प्राइवेट हॉस्पिटल, सोसायटी और सेल्फहेल्प ग्रुप को जनऔषधि केंद्र खोल सकता है।तीसरी कैटेगरी में राज्य सरकारों की ओर से नॉमिनेट एजेंसी जनऔषधि केन्द्र खोल सकती है।

यहां से मिलेगा फार्म

जन औषधि केन्द्र के लिए रिटेल ड्रग सेल्स का लाइसेंस जन औषधि केंद्र के नाम से लेना होता है। इसे खोलने के लिए आपके पास 120 वर्ग फुट की दुकान होनी चाहिए। इसके लिए फार्म यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फार्म डाउनलोड करने के बाद आपको आवेदन ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर (एएंडएफ) के नाम से भेजना होगा।

आरबीआई ने कहा, जीडीपी में इस साल आ सकती है 9.5 प्रतिशत की गिरावट

(एजेंसी) मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में 9.5 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है।मौद्रिक नीति समिति की तीन दिन चली समीक्षा बैठक के बाद रिजर्व बैंक ने यह अनुमान व्यक्त किया। इससे पहले केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी अनुमान के अनुसार पहली तिमाही में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में 23.9 प्रतिशत की गिरावट आयी है। मौद्रिक नीति समिति की बुधवार को शुरू हुई बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस के खिलाफ अभियान में निर्णायक चरण में प्रवेश कर रही है। दास ने कहा, ''अप्रैल- जून तिमाही में अर्थव्यवस्था में आई गिरावट अब पीछे रह गयी है और अर्थव्यवस्था में उम्मीद की किरण दिखने लगी है ...।'' उन्होंने विनिर्माण क्षेत्र और ऊर्जा खपत में तेजी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति भी 2020-21 की चौथी तिमाही में कम होकर तय लक्ष्य के दायरे में आ सकती है। उल्लेखनीय है कि खुदरा मुद्रास्फीति हाल के महीनों में छह प्रतिशत से ऊपर पहुंच गई। आरबीआई मौद्रिक नीति समीक्षा में मुख्य रूप से खुदरा मुद्रास्फीति (सीपीआई) पर गौर करता है। सरकार ने आरबीआई को दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य दिया हुआ है। दास ने कहा कि जीडीपी में चालू वित्त वर्ष में 9.5 प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान है।

सरकार ने दी चुनिंदा प्याज के निर्यात की इजाजत

(एजेंसी) नई दिल्ली । सरकार ने प्याज के निर्यात पर पिछले महीने लगाई गई पाबंदी में ढील देते हुए बंगलोर रोज और कृष्णापुरम किस्म के प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी है। हालांकि, इस छूट के साथ निर्यात के लिए कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में शुक्रवार को कहा कि बंगलोर रोज और कृष्णापुरम प्याज की 10,000 टन मात्रा के निर्यात की इजाजत दी जा रही है। यह इजाजत तत्काल प्रभाव से अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिए वैध रहेगी। इसके अलावा एक शर्त यह भी है कि निर्यात सिर्फ चेन्नई बंदरगाह से किया जाएगा। सरकार ने 14 सितंबर को प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी, ताकि घरेलू बाजार में इसकी आपूर्ति बढ़ाई जा सके और दरों में तेज उछाल पर लगाम लगाई जाए। कर्नाटक के किसानों ने सरकार से 10,000 टन बंगलोर रोज किस्म के प्याज के निर्यात की छूट दिए जाने की अपील की थी, क्योंकि घरेलू बाजार में इस प्याज की मांग नहीं है। इसकी मांग मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान और थाइलैंड जैसे एशियाई देशों में ज्यादा है। बंगलोर रोज प्याज के निर्यातकों को कर्नाटक सरकार के बागवानी आयुक्त से वस्तु और उसकी मात्रा का प्रमाणपत्र लेना होगा। इसी प्रकार कृष्णापुरम प्याज के निर्यातकों को यह प्रमाणपत्र आंध्र प्रदेश की सरकार देगी।

आरबीआई का बड़ा फैसला, दिसंबर से अब सातों दिन, 24 घंटे मिलेगी आरटीजीएस सुविधा

(एजेंसी) मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि बड़ी राशि के अंतरण के लिये भारत में आरटीजीएस (भुगतान के तत्काल निपटान) की सुविधा आगामी दिसंबर से चौबीसों घंटे शुरू कर दी जाएगी।इससे भारतीय वित्तीय बाजार को वैश्विक बाजारों के साथ एकीकृत करने के प्रयासों को मदद मिलेगी। आरबीआई की पुनर्गठित मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय पहली बैठक के बाद जारीसमीक्षा रपट में कहा गया है, भारत वैश्विक स्तर पर ऐसे गिने चुने देशों में होगा जहां 24 घंटे, सातों दिन, बारहों महीने बड़े मूल्य के भुगतानों के तत्काल निपटान की प्रणाली होगी। यह सुविधा दिसंबर 2020 से प्रभावी हो जाएगी। आरबीआई ने इससे पहले दिसंबर 2019 में एनईएफटी प्रणाली (नेशनल इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर सिस्टम) को हर रोज चौबीसों घंटे खुला किया था। रपट के अनुसार एनईएफटी उस समय से चौबीसों घंटे सुचारु रूप से काम कर रही है। आरटीजीएस अभी केवल बैंकों के सभी कार्यदिवसों में (दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़ कर)सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक खुला रहता है। आरबीआई ने कहा है कि आरटीजीएस के चौबीसों घंटे उपलब्ध होने से भारतीय वित्तीय बाजार को वैश्विक बाजार के साथ समन्वित करने के निरंतर जारी प्रयासों तथा भारत में अंतराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों के विकास में की मदद होगी। इससे भारतीय कंपनियों व संस्थाओं को भुगतान में और आसानी होगी। रिजर्व बैंक ने जुलाई 2019 से एनईएफटी और आरटीजीएस के जरिये धन अंतरण पर शुल्क लेना बंद कर दिया था। देश में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिये यह कदम उठाया गया। आरटीजीएस के जरिये बड़ी राशि का त्वरित अंतरण किया जाता है, जबकि एनईएफटी का इस्तेमाल दो लाख रुपये तक की राशि को भेजने के लिये

एसबीआई खाताधारकों के लिए अच्छी खबर, डेबिट कार्ड पर मिल रही सुविधा, कर सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग

(एजेंसी) नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफइंडिया के खाताधारकों के लिए अच्छी खबर है। इस त्योहारी मौसम में आपको अपनी खरीदारी के लिए बैंक बैलेंस देखने की जरूरत नहीं है। एसबीआई अपने खाताधारकों को जारी किए गए डेबिट कार्ड अब ईएमआई सुविधा के साथ दिए जा रहे हैं। इसका फायदा उन ग्राहकों को होगा जो होम अप्लायंसेज या ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं। ग्राहक अपनी खरीदारी को तुरंत किस्तों में बदल सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाताधारकों को दिए जाने वाले डेबिट कार्ड में प्री अप्रूव्ड ईएमआई सुविधा दे रहा है।

आपको यह सुविधा अगर नहीं मिल रही है तो आप इसकी जानकारी बैंक से ले सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डेबिट कार्ड्स में ये सुविधा उपलब्ध न हो। जानकारों के मुताबिक, एसबीआई ने अपने चुंनिदा ग्राहकों के लिए प्री अप्रूव्ड ईएमआई की सुविधा ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी दी है। ग्राहक फ्लिपकार्ट और अमेजन में ये सुविधा ले सकते हैं। कोरोना वायरस संकट के बीच आने वाले इस त्योहारी सीजन में ग्राहकों को खुशियां मनाने के मौके प्रदान करने के लिए अपने खुदरा ग्राहकों के लिए कई सारे स्पेशल ऑफर्स लेकर आया है। इन ऑफर्स का फायदा उठाकर ग्राहक इस त्योहार अपने घर में खुशियां बिखेर सकते हैं। बैंक ने योनो एप के जरिए कार लोन, गोल्ड लोन और पर्सनल लोन के लिए आवेदन करने वाले सभी ग्राहकों के लिए प्रोसेसिंग फीस में 100 फीसद छूट की घोषणा की है। एसबीआई गोल्ड लोन ग्राहकों के लिए भी स्पेशल ऑफर लेकर आया है। इसमें 7.5 फीसद की न्यूनतम ब्याज दर पर 36 महीने तक का लचीला पुनर्भुगतान विकल्प पा सकते हैं।

टीवी के भीष्म पितामह मुकेश खन्ना द कपिल शर्मा पर बुरी तरह भड़के

कॉमेडी का सबसे सफल और मजेदार शो श्द कपिल शर्माश् लगभग हर हफ्ते धूम मचाता है। इस शो की एक खासियत यह भी है कपिल शर्मा शो के किरदार न केवल दर्शकों का मनोरंजन करते हैं,बल्कि लोगों का जमकर मनोरंजन भी करते हैं। वहीं बीते सप्ताह कपिल शर्मा के शो पर महाभारत की कास्ट आई थी,जिसके साथ कपिल शर्मा और अन्य किरदारों ने खूब मस्ती भी की,मगर इस एपिसोड में भीष्म पितामह यानी की मुकेश खन्ना शो पर कहीं दिखाई नहीं दिए। ऐसे में हाल ही में अभिनेता मुकेश खन्ना ने कपिल शर्मा के चर्चित शो में न जानें की वजह सभी को बताई है। दरअसल मुकेश खन्ना ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है,इतना ही नहीं अपनी इस पोस्ट के जरिये मुकेश ने कपिल के शो पर जमकर अटैक किया और इस पॉपुलर शो को उन्होंने एकदम वाहियात और फूहड़ता से भरा हुआ भी बताया है। मुकेश खन्ना ने सोशल

मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपनी बात रखते हुए बताया ये प्रश्न वायरल हो चुका है कि महाभारत शो में भीष्म पितामह क्यों नहीं? कोई कहता है उनको इंवाइट नहीं किया गया। कोई कहता है उन्होंने खुद्द मना किया। ये सच है कि महाभारत भीष्म के बिना अधूरी है। ये सच है कि इंवाइट न करने का सवाल ही नहीं उठता। ये भी सच है की मैंने खुद मना कर दिया था। अब ये भी सच है कि लोग मुझसे पूछेंगे कि कपिल शर्मा जैसे बड़े शो को कोई मना कैसे कर सकता है? बड़े से बड़ा एक्टर जाता है। जाते होंगे, लेकिन मुकेश खन्ना नहीं जाएगा!

मुकेश खन्ना आगे लिखते हैं कि यही प्रश्न गूगी ने मुझसे पूछा कि रामायण के बाद वे लोग हमें इंवाइट करने वाले हैं। मैंने कहा तुम सब जाओ मैं नहीं जाऊंगा। कारण ये कि भले ही कपिल शर्मा शो पूरे देश में पॉप्युलर है। परंतु मुझे इससे ज्यादा वाहियात शो कोई नहीं लगता। फूहड़ता से भरा हुआ, डबल मीनिंग जुमलों से भरपूर, अश्लीलता की ओर हर पल मुड़ता हुआ ये शो है, जिसमें मर्द, औरतों के कपड़े पहनता है। घटिया हरकतें करता है और लोग पेट पकड़ कर हंसते हैं। मुकेश लिखते हैं, इस शो में लोग क्यों हैं करके हंसते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया। एक बंदे को सेंटर में सिंहासन पर बिठा कर रखते हैं। उसका काम है हंसना। हंसी न भी आए तो भी हंसना। इसके उन्हें पैसे मिलते हैं। पहले इस काम के लिए सिद्धु भाई बैठते थे। अब अर्चना बहन बैठती हैं। काम? सिर्फ हा हा हा करना!! एक उदाहरण दूंगा। आप समझ जाएंगे कि कॉमेडी का स्तर कितना घटिया है इस शो में। आप सबने देखा होगा। इसके पहले का रामायण शो। कपिल, अरुण गोविल को पूछता है।

आप बीच पर नहा रहे हो। भीड़ में से एक बंदा चिल्ला कर बोलता है.. अरे देखो-देखो राम जी भी वीआईपी अंडरवियर पहनते हैं! आप क्या कहेंगे? मैंने सिर्फ प्रोमो देखा। उसमें अरुण गोविल जो श्री राम जी की इमेज लेकर घूमते हैं, सिर्फ मुस्कुरा दिए। जिसको दुनिया राम के रूप में देखती है, उससे आप यह घटिया प्रश्न पूछ कैसे सकते हैं! नहीं मालूम अरुण ने जवाब में क्या कहा। मैं होता तो कपिल का मुंह बंद करा देता।

काजल अग्रवाल जल्द बनने वाली हैं गौतम किचलू की दुल्हनियां

साउथ इंडस्ट्री फिल्मों की सुपरस्टार और सिंघम फिल्म की फेमस अभिनेत्री काजल अग्रवाल बहुत जल्द ही शादी करने वाली हैं। इस बात की जानकारी खुद काजल ने अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी है। काजल ने यह पोस्ट शेयर करके बताया कि वो इसी महीने की 30 तारीख को गौतम किचलू के साथ शादी के बंधन में बंधेगी। गौतम पेशे से एक एंटरप्रेन्योर इंटीरियर डिजाइनर हैं।इतना ही नहीं अभिनेत्री ने यह भी जानकारी दी उनकी शादी में सिर्फ परिवार के

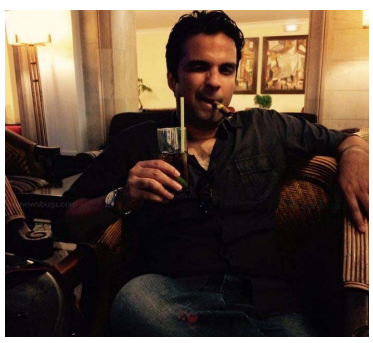

लोग ही शामिल होंगे। वहीं काम की बात को लेकर भी उन्होंने जानकारी देते हुए पोस्ट में बताया कि वो शादी के बाद भी अपना काम करती रहेंगी। अभिनेत्री काजल ने अपनी शादी की जानकारी साझा करते हुए लिखा मुझे बहुत खुशी है कि मैं गौतम किचलू के साथ 30 अक्टूबर 2020 को मुंबई में शादी करने वाली हूं,जिसमें सिर्फ परिवार के लोग ही शामिल होंगे। कोरोना ने निश्चित रूप से हमारे जीवन पर गहर प्रकाश डाला था,परंतु हम लोग एक साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं और हम जानते हैं कि आप लोग भी हमें जरूर चियर करेंगे। मैं आप लोगों को शुक्रिया करती हूं,जो इतने दिनों तक आपने मुझे प्यार दिया और मुझे आशीर्वाद दिया। लेकिन जैसे कि हम अपनी लाइफ का नया सफर शुरू करने जा रहे हैं तो हमें आपकी दुआओं की सबसे ज्यादा जरूरत है। आगे काजल ने लिखा मैं वो सभी चीजें जारी रखूंगी जो मैं अब तक करती आई हूं। अपने दर्शकों का मनोरंजन करना एक नई उम्मीद और नए तरीके के साथ। आप लोगों के साथ के लिए धन्यवाद। वर्कफ्रंट की बात करें तो काजल जल्द ही कमल हसन की फिल्म इंडियन 2 में दिखाई देंगी। इसके अलावा अभिनेत्री के हाथ दलकीर सलमान और अदिति राव हैदरी की फिल्म हे सिनामिका भी है।

ट्विटर पर शुरू हुई अक्षय कुमार की फिल्म को बैन करने की मांग

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत मामले में खुल कर अपनी बात सबके सामने रखी थी। उन्होंने अपनी इस वीडियो में बॉलीवुड का सपोर्ट करते हुए सबको एक ही तरह न देखने की बात की थी। दरअसल, उन्होंने वीडियो में बॉलीवुड का साथ दिया है और कहा है कि ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड से जुड़े सभी लोग ड्रग्स लेते हैं।

इस पर कई बॉलीवुड हस्तियों ने अक्षय कुमार का साथ दिया है। अक्षय कुमार का ड्रग्स कनेक्शन को लेकर कहना है कि ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में ड्रग्स की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इसका मलतब ये नहीं है कि सभी लोग ड्रग्स लेते हैं। अब अक्षय कुमार का बॉलीवुड सेलेब्स के पक्ष में बोलना कुछ लोगो को पसंद नहीं आ रहा है और वो अक्षय कुमार के वीडियो का विरोध कर रहे हैं। इतना ही इन लोगों ने ट्विटर पर एक मुहिम भी चलाई है, जिसमें अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को बैन करने की मांग कर रहे हैं। लक्ष्मी बॉम्ब को बैन करने के लिए हैशटैग के साथ ट्वीट किए जा रहे हैं और अब ये टॉप ट्रेंडिग हैशटैग में शामिल हो गया है, यानी हजारों लोग इस पर ट्वीट कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अक्षय कुमार की फिल्म का बहिष्कार किया जाना चाहिए। हो सकता है की अगर लोगो में अक्षय को लेकर गुस्सा इसी तरह बढ़ता रहा तो उनकी फिल्म भी सड़क 2 की तरह फ्लॉप हो जाए।

दिशा पटानी की बोल्ड तस्वीर ने सोशल मीडिया पर मचाया कोहराम, शानदार कमेंट की हुई बौछार

अपनी बोल्डनेस से लाखों दिलों पर राज करने वाली बॉलीवुड अदाकारा दिशा पटानी सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। दिशा अक्सर अपने फैंस के लिए एक से बढ़कर एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करती रहती हैं जिन्हें उनके चाहने वाले बहुत पसंद भी करते हैं। इसी वजह से इंस्टाग्राम पर दिशा पाटनी को 40 मिलियन फैंस फॉलो करते हैं। हाल ही में दिशा ने सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो साझा की है,जिसे देख अभिनेत्री के फैंस काफी ज्यादा खुश हैं। दरअसल अदाकारा ने अपने इंस्टा पर एक फोटो शेयर कहै,जिसमें वो पीले रंग का स्विमसूट पहने दिख रही हैं। अब ऐसे में दिशा के फैंस उनकी तरीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं। एक फैन ने दिशा को कमेंट करते हुए उनकी सराहना की और लिखा हिरन भी शरमा जाए ऐसी खूबसूरती। वहीं एक अन्य यूजर तारीफ करते हुए कमेंट किया पीला रंग आप पर बहुत जंचता है। तो वहीं किसी का कहना था कि आप बहुत प्यारी हो। वैसे दिशा पटानी की सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस बेहद खूबसूरत फोटो को इंस्टाग्राम पर 19 लाख 23 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं,जबकि 14 हजार से ज्यादा लोगों ने इस पर कमेंट किया है। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो दिशा पटानी की आगामी फिल्म राधे में सलमान खान के साथ दिखाई देने वाली हैं। इसके अलावा अदाकारा मोहित सूरी की फिल्म एक विलेन 2 में भी नजर आएंगी।

Scholarship & Fee - reimbursement schemes available for all caste categories for all courses.

REGISTRATION / ADMISSION OPEN

ARYAKUL GROUP OF COLLEGES

ARYAKUL COLLEGE OF PHARMACY & RESEARCH
Code : 316
PCI Approved

B.PHARM | M.PHARM Pharmacology/Pharmaceutics/Pharm. Chemistry

- DIRECT ADMISSION in B.Pharm: *Eligibility* - 10+2 Level Examination or its equivalent securing Minimum 50% (45% for S.C./S.T.) Marks in total or required subject combination Physics, Chemistry & one Optional (Maths/Biology/Computer Science).
- DIRECT ADMISSION (LATERAL ENTRY) TO 2nd year in B.PHARM FOR 2/3 YEARS DIPLOMA HOLDERS IN PHARMACY WITH 50% MARKS.
- **FREESHIP OF TUITION FEE**- Provision for girls, economically weaker section (EWS) as defined by GBTU & physically handicapped meritorious students.
- **Eligibility For M.Pharm** : B.Pharm with 45% for SC/ST & 50% marks for gen./obc/min.

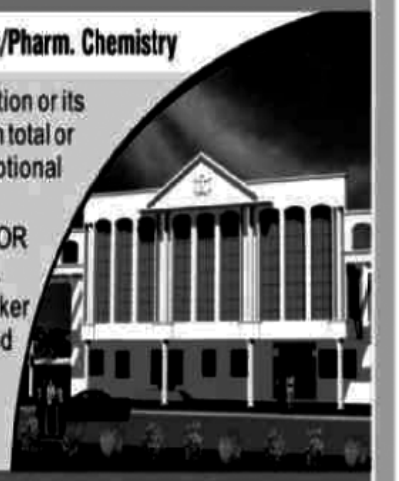

ARYAKUL COLLEGE OF MANAGEMENT
Code : 396

MBA (2 YEARS) Eligibility- Graduation with 45% for SC/ST & 50% for General & OBC
PGDM (2 YEARS) Eligibility- Graduation with 45% for SC/ST & 50% for General & OBC

Best Placement Assistance

ARYAKUL COLLEGE OF EDUCATION
- B.B.A. Eligibility- Intermediate with 45% for SC/ST & 50% for General & OBC
- B.J.M.C. Eligibility- Intermediate with 40% for SC/ST & 45% for General & OBC
- B.T.C. Basic Teachers Certificate (2 Years)

Natkur, P.O. Chandrawal, Aryakul College Road
Adjacent to CRPF Base Camp, Lucknow-02 (4KMs from Amausi Air Port), UP, INDIA
Email: aryakulcollege@gmail.com, Website: www.aryakul.org.in
Ph.: 094153-23205, 090050-92455, 090050-92460, Ph./ Fax : 0522-2817724

IN CAMPUS HOSTEL WITH THE FACILITY OF RECREATION ROOM
TRANSPORT FACILITY AVAILABLE FROM VARIOUS POINTS OF THE CITY TO THE COLLEGE.

इस अखबार के लिए जरूरत है इन्टर्न और संवाददाताओं की
हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करें
9919892139, 7843927624
Email : bachpanexpress@gmail.com

Visit : www.utsawdeals.com
Email : callinganandravi@gmail.com
www.facebook.com/utsavdeals

उत्सव Deals

Event Management, P.R. & Advertising Services

CORPORATE EVENTS
SOCIAL EVENTS
SEMINAR
CONFERENCE
MARRIAGE PARTY
BIRTHDAY PARTY
FRESHER PARTY
FAREWELL PARTY
STAGE SHOW
MUSICAL SHOW

We Provide
A Vehicle, A Hotel, Venue, Tent Decorations, Flower Decor, House Lighting, Videography, Catering Service, DJ, Band-Baja, Dhol, Entertainment, Dance Group and anything else you need.

सारा अरेंजमेंट एक साथ आपके द्वार.....

Call: +91-9473649690, 8381960029, 9450231395

DK
TENT HOUSE

Dinesh Kumar - 9839903697
Vibhav Kumar - 9506257029

Add.:
1/72, Piprouli, South City Complex,
Behind Lucknow Public School,
Raebareli Road, Lucknow-226025

E-mail : dk.tent.1987@gmail.com

अधिक जानकारी के लिए हमे सम्पर्क करें।
हेड आफिस: ई–998, रत्नाकर खण्ड, शारदानगर, रायबरेली रोड, लखनऊ
ब्रान्च ऑफिस: सी–9/15ए–1, फातमान रोड मालदहिया, वाराणसी–221002
ई–मेल: bachpanexpress@gmail.com, web : bachpanexpress.in/com
मो. नं. 9919892139, 7843927624

BACHPAN EXPRESS
बचपन एक्सप्रेस

स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक मीना पाण्डेय के लिए सीमना प्रिंटिंग प्रेस, नजरबाग हुसैनगंज, कैंट लखनऊ से मुद्रित एवं बी 2/1–2 बी टाईप रेजीडेन्सी, बीबीएयू, लखनऊ से प्रकाशित। प्रधान कार्यालय: ई–998, रत्नाकर खण्ड, शारदा नगर लखनऊ 226025
प्रधान संपादक **मीना पाण्डेय**, सम्पादकीय सलाहाकर **प्रो. गोविन्द जी पाण्डेय**, सलाहकार संपादक **नीलू शर्मा**, सलाहकार समाचार संपादक **श्वेता सिंह**, सलाहकार **अनुकृति**, संपादक **पुष्कर प्रताप सिंह**, ई–मेल: **bachpanexpress@gmail.com, web : bachpanexpress.in/com**
सम्पर्क सूत्र – 7843927624